# RAJYA SABHA

*Thursday, the 4th November, 1982/ 13th Kartika 1904 (Saka)*

The House met at eleven of the clock **Mr. Deputy Chairman** in the Chair.

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों की स्थापना

*341. **श्री रामेश्वर सिंह :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, और बलिया में उनके मंत्रालय के अधीन कोई सरकारी क्षेत्र के उपक्रम स्थापित करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) उत्तर प्रदेश मे ऐसे महत्वपूर्ण औद्योगिक नगरों की संख्या कितनी है जहां सरकार ने सरकारी अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है और प्रत्येक मामले में विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन औद्योगिक घरानों के नाम क्या हैं जिन्होंने इन नगरों में गैर सरकारी प्रतिष्ठान अथवा उद्योग स्थापित करने की अनुमति मांगी है।

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह)** : (क) से (ग) उद्योग मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया का मिर्जापुर जिले में 6.60 लाख मी0 टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाले एक सीमेंट कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(घ) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के अधीन जारी किए गए सभी आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों के ब्यौरे जिनमें उपक्रम का नाम, स्थापना स्थल, उत्पादन की वस्तु और क्षमता आदि होता है प्रकाशित किए जाते है। कुछ दैनिक पत्रों के अलावा भारतीय निवेश केन्द्र अपने पत्र "मन्थली न्यूजलैटर" में इन ब्यौरों को प्रकाशित करता है। इनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में प्राप्त है।

(ङ) वर्ष 1982 (सितम्बर तक) के दौरान एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियों को तीन औद्योगिक लाइसेंस तथा 2 आशय पत्र जारी किए गए थे। इसके अलावा सितम्बर, 1982 तक एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत विभिन्न कम्पनियों से उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना करने के बारे में आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के संबंध मे प्राप्त आवेदन पत्रों में से 20 आवेदन पत्र इस समय विचाराधीन है।

**श्री रामेश्वर सिंह** : मंत्री जी ने सवालों का जवाब न दे कर एक रिपोर्ट पढी, तो मैं भी रिपोर्ट लाया हूं...

**श्रीमती राम दुलारी सिन्हा** : आप सवाल ही पूछिये।

**श्री रामेश्वर सिंह** : मैं सवाल ही पूछूंगा। उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी है। मैं

बहुत मार्मिक शब्दों मे और बहुत ही संतुलित भाषा में अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूं और सवाल पूछना चाहता हूं।

श्रीमन्, क्या यह सही नहीं है कि जिस इलाके से मैं आता हूं, बलिया जिला, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बनारस, मिर्जापुर, यह सब ऐसे पिछड़े इलाके है कि जहां आजादी के बाद भी आज तक गोबर से निकाला हुआ अन्न लोग खाते हैं और वहां की आज जो हालत है वह कही नहीं जा सकती। संपूर्ण देश में जो प्रति व्यक्ति इन्कम है वह हमारी 197 रुपये कुछ पैसे है। यह हमारे यहां की स्थिति है। श्रीमन्, स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरु जी ने एक पटेल आयोग नियुक्त किया था उद्योगों का सर्वेक्षण करने के लिए। तो मेरा यही सवाल है कि उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी है और यह पटेल आयोग श्री जवाहर लाल जी ने अशोक मेहता जी उस समय प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे, तो क्या यह सही नहीं है कि 1962 में उन्होंने एक कमेटी बनायी थी पूर्वी जिलों--बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर आदि का सर्वेक्षण करने के लिए, जौनपुर, देवरिया आदि के लिए और उस रिपोर्ट में है जिस को यह पढ़े हैं और सारा मैं पढ़ू तो बहुत सा समय चला जायेगा और उस में भी पूरा नहीं होगा, तो मैं सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता.....

**श्री सभापति** : उन को अलग ले जा कर सुना दीजियेगा। लेकिन पूरी रिपोर्ट न सुना देना।

**श्री रामेश्वर सिंह** : तो मैं सुनाये दे रहा हूं। (*व्यवधान*) मैं क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं। आप घबराइये मत। क्या यह सही नही है कि जो भी मंत्री बना है उस ने अपने ही क्षेत्र का विकास किया है, चाहे वह प्रधान मंत्री जी हों...

**श्रीमती इंदिरा गांधी** : बिलकुल सच नहीं है। बिलकुल सच नहीं है। I strongly protest against it.

**श्री रामेश्वर सिंह** : अगर यह बात सही नहीं है तो इलाहाबाद का विकास हो गया, नैनी का। मैं प्रधान मंत्री जी से बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि मैं आप को बहुत इज्जत करता हू और मैं आप से अपेक्षा रखता हूं, उम्मीद रखता हूं, आप जानती हैं कि आजादी की लड़ाई में बलिया जिले में सब से पहले हुकमत पर कब्जा किया गया और स्वर्गीय चित्तू पांडे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हुकूमत पर कब्जा कर के वहां आजाद सरकार कायम की थी।

**श्री जे० के० जैन** : लम्बा चौड़ा भाषण देकर ये सदन का समय बरबाद कर रहे हैं।...(*व्यवधान*)

**श्री सभापति** : गोयम मुश्किल न गोयम मुश्किल।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : जो बलिया के बारे में कह रहे हैं वह सच है, हम सब को चित्तू पांडे का बहुत आदर है।

**श्री रामेश्वर सिंह** : तो मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का शुक्रगुजार हूं कि...

**श्री सभापति** : जल्दी करिये, सवाल पूछिये।

**श्री रामेश्वर सिंह** : मैं जानना चाहता हूं कि 30-32 वर्ष में बलिया जिले में क्या कारण था कि अभी तक कोई भी उद्योग आपने नहीं लगाया जब कि स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू, मैं उनकी इज्जत करता हूं, उन्होंने कमेटी बनाई थी। तो इस रिपोर्ट पर क्या अमल किया गया है?

**श्री सभापति** : आपने सवाल पूरा कर दिया अब बैठ जाइये ।

**श्री रामेश्वर सिंह** : क्या जो सर्वेक्षण वहां पर हुआ था उसके मुताबिक कोई उद्योग लगाया है और नहीं लगाया है तो क्यों नहीं लगाया है ? दूसरा सप्लीमेंटरी मैं बाद में पूछूंगा ।

**श्री नारायण दत्त तिवारी** : श्रीमन् जो सम्मानित सदस्य ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों की विषम आर्थिक स्थिति का चित्रण किया है, वह चाहे तथ्यों में उतना सही न हो, लेकिन वह एक वास्तविकता है और इसीलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का, देश के अन्य पिछड़े भागों के साथ साथ, विकास का प्रयत्न किया जा रहा है ।

जहां तक पटेल आयोग का प्रश्न है, उसका अध्ययन मुझे स्वयं करने का मौका कई बार मिला और इसकी जो कई सिफारिशें हैं उससे कहीं आगे हम बढ़ रहे हैं ।

जहां तक पटेल आयोग ने कहा था कि 8 नई चीनी मिलें बनाई जायें और उसमें उन्होंने जो उल्लेख किया था उसके अनुसार चीनी मिलें बनाई जा रही हैं । आजमगढ़ में एक चीनी मिल साठा पर बन चुकी है । खोसी में बनाई जा रही है । जो स्पिनिंग मिल्स बनाई जा रही हैं, एक मऊनाथ भंजन में बन चुकी है, मगहर में बन चुकी है, फैजाबाद में, बाराबंकी में स्पिनिंग मिल बन चुकी है और आगे भी इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बागास बेस्ड एक पेपर प्लांट स्थापित किया जाये । इसका सर्वे हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की ओर से चल रहा है । गाजीपुर, आनन्दगन्ज में चीनी मिल बन चुकी है । गाजीपुर में गंगा पर पुल नहीं था, अब वह पुल बन रहा है उससे गाजीपुर के औद्योगीकरण में आसानी होगी । गाजीपुर में 'सेल' की ओर से एक स्टील पलांट 12 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया जा रहा है । उसकी मैकोन के द्वारा फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जा रही है । रसड़ा में एक चीनी मिल स्थापित हो चुकी है । इसके अलावा बलिया में इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि जो नये लाइसेंस दिये जायें उसमें उत्तर प्रदेश शासन को कहा जा रहा है कि सारे बैकवर्ड जिलों को जो लाइसेंस दिये जाते हैं वह ऐसे होते हैं जो बैकवर्ड जिलों में एरियाज में लगाये जायें, इनके लिये क्षेत्र नामांकित नहीं होते । तो उत्तर प्रदेश सरकार को कहा जा रहा है कि जो अनामांकित लाइसेंस है ये अधिकांशतः पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन जिलों को दिये जायें, उन क्षेत्रों को दिये जायें जहां पर कोई उद्योग धंधा अभी तक नहीं है । जो 9 डिस्ट्रिक्टस है उनमें 13 लाइसेंस और 8 बैकवर्ड के, कुल 21 नये लाइसेंस दिये गये है और उत्तर प्रदेश शासन को यह अधिकार है कि स्थान का चयन करे । तो हमने उत्तर प्रदेश शासन को नीतिगत सुझाव दिया है कि वह इन्हीं स्थानों पर उद्योग लगाये जैसे अन्य प्रदेश सरकारें अपने यहां के पिछड़े क्षेत्रों के विकास का प्रावधान करती हैं ? उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में दो नयी प्रैस्टिज योजनायें चालू की है प्रैस्टिज यूनिट्स और पाइनियर यूनिट्स की । उन्होंने इसके लिये तहसील को यूनिट माना है और जिन जिलों या तहसीलों में ऐसी पाइनियर इकाई अगर हैं तो 15 प्रतिशत सबसिडी उत्तर प्रदेश अलग से उसको देगी । जो प्रैस्टिज यूनिट्स हैं अगर 20 करोड़ से ऊपर की हैं उनको अलग से सबसिडी दी जायेगी । इसकी पूरी रिपोर्ट मेरे पास है जो हाल में उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने नये अवसर दिये हैं । वह रिपोर्ट मैं अलग से उपलब्ध करा सकता हूं । इसका पूरा

विवरण है। इस बात का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का पिछड़ा भाग, विशेष तौर से जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां पर उस दिशा में कार्य किया जाये। मैं सम्मानित सदस्य और सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनके विकास के लिये हर संभव प्रयास किया जायेगा।

श्री रामेश्वर सिंह : श्रीमन्, मंत्री जी ने रसड़ा चीनी मिल का जिक्र किया है बलिया में। उस चीनी मिल की हालत यह है कि वह प्रायः चीनी मिल बन्द रहती है।

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य: यही वजह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में उद्योग नहीं हैं। काम ही नहीं करने देते।

श्री रामेश्वर सिंह : ये मिल अक्सर बन्द रहती हैं। चीनी मिल का क्या विकास होगा जब वह बन्द रहेगी। आज भी लोगों को गोबर से अन्न निकाल कर खाना पड़ता है। (व्यवधान)

श्री सभापति : इतनी बड़ी कथा लेकर बैठ गये। सवाल पूछिये।

श्री रामेश्वर सिंह : सवाल ही पूछ रहा हूं। यह उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं और अब उद्योग मंत्री हैं सौभाग्य से। आप आगे बढ़ें मुझे खुशी होगी। आपने कहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं। आपने बलिया का जिक्र नहीं किया फिर भी मैं पूछना चाहता हूं कि बलिया की जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें क्या इसे कृषि प्रधान जिला बताया गया है, रेलवे के आवागमन के साधन के लिये बेस लाइन है, तो वहां सर्वे रिपोर्ट में इसके लिये कोई सुझाव दिया? क्या मछली पालन की और डेरी फार्म की योजना को लागू करने के लिये सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है? अगर विचार कर रही है, तो कब तक इसको पूरा करेगी? साथ ही मैं आप से यह भी पूंछना चाहता हूं कि आपने गिना दिया कि सर्वमुखी विकास हुआ। अगर सर्वमुखी विकास हुआ तो आज यह दयनीय स्थिति क्यों है। इस दयनीय स्थिति को खत्म करने के लिये सरकार कौन-कौन सी योजना वहां लागू करने जा रही है इस छठी पंचवर्षीय योजना में? मैं इस बात को कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि जवाहर लाल जी का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कम से कम एक रिपोर्ट हमारे सामने रख दी। उस रिपोर्ट में यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बलिया जिला में दयनीय स्थिति सबसे खराब है। जहां पर आज लोगों को प्रतिवर्ष पर-कैपिटा इन्कम 197–198 रूपये है। मैं पुनः सरकार से मांग करूंगा और माननीय प्रधान मंत्री जी से आग्रह करूंगा विशेषतौर से कि वह जब भी बलिया जाती हैं तो चिन्तू पांडे की वाइफ से मिलती हैं। आप उनको बुलवाती हैं। केवल बुलवा कर हम को संतोष देती हैं पर जितना करप्शन और भ्रष्टाचार इस देश में फैला हुआ है... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: No, this is not a question. (*Interruptions*).

श्री रामेश्वर सिंह : आप क्यों हल्ला करते हैं। इसी कारण तो बलिया का विकास नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: There is only one way of stopping you. आपके मुंह को बन्द करने का एक ही तरीका है आप जो कहेंगे लिखा नहीं जायेगा। आपको जो सवाल करने हैं, करिये और बैठ जाइये।

श्री रामेश्वर सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप वहां मत्स्य पालन,

डेरी फार्म और बलिया में छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का कोई बड़ा प्लान बनायेंगे जिससे वहां के लोगों को राहत दी जा सके ? यही थोड़े से सवाल जानना चाहता हूं विशेष तौर से प्रधान मंत्री जी से ।

**श्रीमती इंदिरा गांधी** : मैं आपकी इजाजत से कुछ कहना चाहती हूं । मैं बलिया के विषय में कुछ नहीं कह रही हूं यह हम सब को मालूम है कि बलिया का योगदान आजादी की लड़ाई में बहुत ही चमत्कारिक था और हम सब उत्तर प्रदेश वाले और दूसरे भारत के लोगों को इस पर गर्व है । इस समय चर्चा है उद्योग लगाने की । उद्योग लगाने की हमारी एक स्कीम थी वहां पर, जिसे हम बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। सच यह है कि जिस तरह से चालू होनी चाहिये उस तरह से नहीं हुई। जब हमने 80–81 का नक्शा भारत का देखा तो देखा कि अधिकांश उद्योग भारत के कुछ हिस्सों में लगे थे । तो केवल बलिया में ही नहीं, राजस्थान में करीब-करीब कुछ नहीं है, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा इलाका है जहां कुछ नहीं है, बिहार में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में देवरिया की बात उठाई जा रही है और कई लोगों ने अपने-अपने जिलों की बात उठाई । इसलिए केवल बलिया ही नहीं है, जहां नहीं कुछ है, बहुत-से ऐसे इलाके हैं । अब हमारी कोशिश है कि जहां कोई उद्योग नहीं है उसको हम महत्व दें । लेकिन यह बात मेरे लिए कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है । इसलिए कि कल ही लोक सभा में गुल मचा कि एक चीज जा रही थी कहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूं, कहीं न कहीं जा रही थी, उसको वहां क्यों बदला गया, क्यों उत्तर प्रदेश में उसको ले जा रहे हैं क्योंकि इन्फ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा इत्यादि सब ज्यादा ठीक, अच्छा वहां पर है और बहुत सहूलियतें मिली हैं । तो यह एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसको किसी तरह से पार करना है क्योंकि अगर हमें पिछड़े हुए जिलों को बनाना है तो शुरू से शुरू करना है । इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो महंगा जरूर ज्यादा होगा, कठिनाई ज्यादा होगी । लेकिन हमारी नीति है कि उस सब का सामना करें, तब भी वहां आगे बढ़ें । जैसा मैंने लोक सभा में कहा, अगर यह नहीं करेंगे तो किसी सूरत में पिछड़े हुए इलाके कभी अपना पिछड़ापन छोड़ नहीं सकते है । लेकिन यह बात नहीं है कि जितनी एक्सपर्ट कमेटीज हैं या दूसरे हैं वे यही कहते हैं कि ये वायेबल नहीं हैं, खर्चा ज्यादा बढ़ेगा, इत्यादि । इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना है ।

**श्री रामानन्द यादव** : सभापति जी, जब हम उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की बात करते हैं जहां पर सबसे ज्यादा संसार की घनी आबादी है और सबसे अधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं और जहां के लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है और जो एग्रो बेस्ड एरिया है, तो साथ ही बिहार के और खासतौर से उत्तरी बिहार के हिस्सों को भी हम नहीं भूल सकते हैं । इन दोनों की जमीन और विकास एक समान है । केवल एक ही इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में और बिहार के उत्तरी जिलों में है और वह है शुगरकेन इंडस्ट्री और केवल इस बात की संभावना है कि वहां पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ही कायम हो सकती है, जिसकी चर्चा माननीय मंत्री जी ने की है । मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत सी प्रोजेक्ट्स को वहां पर टेकअप किया गया है । मंत्री जी ने कहा कि वहां पर बगास वैस्ड पेपर मिलें खोली जा सकती हैं । मैं मंत्री महोदय से यह

जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में और बिहार के उत्तरी हिस्सों में जहां पर शुगर मिलें हैं वहां पर जो पेपर मिलें होंगी वे बगास बैस्ड होंगी या हर जगह बगास को लेकर फैक्ट्रीज खोली जाएंगी ? क्या सफिशिएन्ट बगास उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में और बिहार के उत्तरी जिलों में मिल जाएगा ? क्या सरकार इस बात पर भी विचार करेगी कि बगास बेस्ड जो फेक्ट्रीज होंगी उनकी केपेसिटी इतनी इंक्रीज की जाएगी कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में और बिहार के उत्तरी जिलों में जहां पर इस प्रकार मिलें होंगी वे पूरी केपेसिटी से बगास का इस्तेमाल कर सकें ?

**श्री नारायण दत्त तिवारी** : श्रीमन्, माननीय सदस्य ने बगास के ऊपर आधारित कागज मिलों का उल्लेख किया है। जैसा मैंने कहा, अभी सर्वे चल रहा है। जो अनुभव तमिलनाडु का है क्योंकि वहां पर इस प्रकार की फैक्ट्री लगाई जा रही है और कर्नाटक में एक मिल पहले से ही स्थापित है । बगास का इस्तेमाल चीनी बनाने के लिए बोयलरों में भी होता है । प्रश्न यह है कि कितना बगास बचाया जा सकता है । जो चीनी मिलों की आवश्यकता है, जो कच्चा माल है, उसके अतिरिक्त कितना बगास कागज बनाने के लिए बचाया जा सकता है। इसका सर्वे हो रहा है । सर्वे के बाद बगास की जितनी इकनोमिक युनिट, आर्थिक इकाई उपलब्ध हो सकेगी उतनी बगास मिलों को देने की गुंजायस हो सकती है। बिहार में इस बात का सर्वे हो रहा है और सर्वे के बाद ही निर्णित किया जा सकेगा कि कितने चीनी मिलों के बगास के ऊपर पेपर युनिट्स बनाये जा सकते हैं ।

**श्री सुधाकर पाण्डेय** : श्रीमन्, कुछ दिन पहले बनारस में एक सर्वेक्षण किया गया था, बी० एच० ई० एल० की एक यूनिट लगाने के बारे में। उस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि विभिन्न विभाग विकास के बहुत से काम कर रहे है, उनके को-आर्डिनेशन के लिये, उनके औद्योगिक कोआर्डिनेशन के लिये मंत्री जी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये क्या कोई विकास निगम या औद्योगिक विकास निगम बनायेंगे ?

**श्री नारायण दत्त तिवारी** : श्रीमन्, यह सही है कि बी० एच० ई० एल० की ओर से वाराणसी में एक स्पेयर पार्टस बनाने की यूनिट, एक मीडियम इकाई बनाने का प्रस्ताव है । कठिनाई यह है कि भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जो वहां मडुवाडीह का क्षेत्र है उस भूमि का सर्वेक्षण चल रहा है और उत्तर प्रदेश शासन से यह आग्रह किया गया है कि यह जमीन वह इसके लिये उपलब्ध कराये ताकि स्पेयर पार्ट्स बनाने के बाद जहा जहां उनकी आवश्यकता है वहां भेजा जा सके, सप्लाई किया जा सके. इसलिये जैसे ही भूमि का चयन हो जायेगा तब यह काम शुरू होगा । अभी करीब महीने दिन से कोई सूचना बी० एच० ई० एल० की ओर से प्राप्त नही हो सकी है, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है, यह इसके पहले की जानकारी है और उसके आधार पर निर्णय तो हो चुका है और भूमि मिलते ही उस पर काम शुरू हो जायेगा ।

जहां तक निगम बनाने की बात है जो कि समन्वय करे, विद्वान सदस्य को जानकारी है कि इस प्रकार के निगम उत्तर प्रदेश शासन ने प्रत्येक डिवीजन के लिये, पहले पूर्वांचल विकास निगम पूर्वी यू०पी० के लिये या अब प्रत्येक डिवीजन में एक निगम इस प्रकार

के समन्वय के लिये बना हुआ है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में तीन डिवीजनल कारपोरेशन हैं, इसके अलावा प्रादेशिक स्तर पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन, स्माल स्केल इंडस्ट्री कारपोरेशन, स्पोर्ट्स डेवलपमेन्ट कारपोरेशन, इस तरह के जो प्रादेशिक स्तर पर कारपोरेशन हैं के अलग से समन्वय करते हैं ।

SHRI V. GOPALSAMY : Mr. Chairman, I appreciate the efforts taken by the Government to develop industrially backward States. But, Sir, this should not be at the cost of development of other States.

The hon. Prime Minister just now referred to the statement made by her in the other House yesterday. This concerns Tamil Nadu because a colour film project was to be established in Ooty in Tamil Nadu....

MR. CHAIRMAN: I cannot enlarge the question to take up every State.

SHRI V. GOPALSAMY : But the hon. Prime Minister just now referred to it.

MR. CHAIRMAN : You have not understood her. The hon. Prime Minister said that when she supported something for Uttar Pradesh she was told that U.P. is a very developed State....

SHRI V. GOPALSAMY : No, Sir. She referred in her statement to infrastructure and economic viability. The question of backwardness should be looked into. In Tamil Nadu the Nilgiri district is totally backward. It is inhabitated by tribals, namely, the Badagas. I would request the hon. Minister to kindly reconsider the decision.

MR. CHAIRMAN : I do not think that this question admits references to all sorts of things.

SHRI V. GOPALSAMY : Sir, the colour film project will now be located in Nainital which happens to be the home district of our Industries Minister. I would like to know whether the Minister will reconsider his decision because this has caused resentment in the minds of all political parties in Tamil Nadu and they have submitted a joint memorandum. Therefore, I would like to know from the Minister whether he will reconsider any such decision. He said that it is a new unit.....(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please sit down.

SHRI V. GOPALSAMY : The expert committee has already recommended that the new unit should be located in Ooty. Sir, I want a categorical reply from the Minister.

MR. CHAIRMAN : You have put in your own question about Ooty, Kodaiknal and other places. I am afraid.....

SHRI V. GOPALSAMY : Sir, I seek your protection.

MR. CHAIRMAN : I cannot give you protection when you do not need any protection.

SHRI V. GOPALSAMY : This matter has created serious concern throughout Tamil Nadu.

MR. CHAIRMAN : That is all right.

SHRI V. GOPALSAMY : He has said that this is a new unit. The Nilgiri district is also industrially backward. Tribals are living there and unemployment problem is also there. So I would like to know whether the expert committee has also recommended that Ooty is the proper and suitable place for this project. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN : Just a minute. I have to rule about the relevancy. Please sit down. I do not think this matter arises out of this question. I rule it out. (*Interruptions*)

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: In relation to what the Prime Minister said that backward areas where industries have not been set up will be taken into consideration when new industries are being set up. I would like to draw his attention to the fact that Rs. 16000 crores are invested in the public sector, out of which Jammu and Kashmir's share is only Rs. 5-6 crores. Will the hon. Minister, while taking into consideration the backward areas, look into this aspect, so far as Jammu and Kashmir.... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : I think you better promise to all the States that you are.... (*Interruptions*) What I said about Mr. Gopalsamy also applies to you. We cannot go to Jammu and Kashmir, and not stop at Simla. (*Interruptions*)

SHRI U.R. KRISHNAN : I would like to know from the hon. Minister whether it is a fact that two industries which were originally set up in Tamil Nadu--one which was originally proposd to be set up in Tamil Nadu under Bharat Electronics Limited and one under Hindustan Photo Films-- are likely to be put up in Uttar Pradesh and, if so, what are the reasons for it?

SHRI PILOO MODY : He has connected it. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Are these two projects going to be implemented in Uttar Pradesh or in Tamil Nadu? Only this much may be answered. (*Interruptions*)

SHRI NARAYAN DATT TIWARI : I would request the hon. Member to be rather cautious about facts. Whenever there are any proposals to set up any undertakings, the State Governments are informed that these units will be set up in their respective States. The locational aspect is looked into at he stage when the Project Report has been prepared and the Board recommends a particular location. Then only the Government takes a decision on the recommendation of the Board.

MR. CHAIRMAN : So there is no decision yet. (*Interruptions*)

SHRI V. GOPALSAMY : What about Ooty? (*Interruptions*)

SHRI NARAYAN DATT TIWARI : I am replying to that particular question. There is no question of shifting any unit from any State to any other State. There is no question. The Hindustan Photo Films is there in Ootacomund since 1962. They have another campus at Perambur in Madras. So far as these three units are concerned, we are expecting a recommendation from the Board and then a decision will be taken.

SHRI V. GOPALSAMY : The Committee has recommended Ooty. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please sit down. The answer has been very correctly given that already there is one unit in Ooty and the question whether another should be set up in another place is receiving attention. It does not mean that they are shifting these two.

SHRI V. GOPALSAMY : Not shifting. The Committee recommended.. (*Interruptions*) that the the new unit should also be located at Ooty. Now they have taken a decision....

MR. CHAIRMAN : He has denied the allegation. (*Interruptions*)

श्री कलराज मिश्र : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने पटेल आयोग की

सिफारिशों को लागू करने के सम्बन्ध में कुछ बात बताई । मैं यह जानना चाहूंगा, पटेल आयोग का सर्वेक्षण क्षेत्र जो था वह पाच जिले थे पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर और देवरिया । इन पांच जिलों के सर्वेक्षण के पश्चात् जो उन्होंने रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट के अन्तर्गत विशेष तौर पर गाजीपुर, जौनपुर और आजमगढ़ क्षेत्र के सम्बन्ध में यह बात कही गयी थी कि वहा पेपर मिल की भी स्थापना होनी चाहिए, गाजीपुर में फर्टिलाइजर फैक्टरी की स्थापना होनी चाहिए क्योकि उस प्रकार के कुछ साधन भी उपलब्ध हैं, इस प्रकार की कुछ बातें कही गयी थीं । पिछले शासन के दौरान यह भी बात उठी थी कि जौनपुर जिले में ऊन की फैक्टरी लगनी चाहिए । इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय कुछ बता सकेंगे ? अभी हमारे मित्र रामेश्वर सिह जी ने कहा कि गाजीपुर, बलिया ऐसा क्षेत्र है जहां हम बड़े डेरी फार्म स्थापित कर के आसपास के जिलों में दूध की आपूर्ति कर सकते हैं । क्या मंत्री महोदय वहां इस प्रकार का उद्योग स्थापित करने की बात सोच रहे है ?

**श्री नारायण दत्त तिवारी** : : श्रीमन्, जैसा . . .

**श्री सभापति** : आप के जवाब में था, आप ने कहा ।

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: Everything will be put up in UP. Why are you worried. So, let us go on to the next question.

SHRI PILOO MODY : Let us go to the next question.

**श्री नारायण दत्त तिवारी** : : जी हां, मैंने यह उत्तर दिया कि बी० पी० पटेल साहब की रिपोर्ट 62 में दी गयी थी । उसके बाद और दिशाओं में भी प्रगति हो चुकी है । पहले पांच जिले थे, उस के बाद आठ जिले कर दिये गये । मैं ने इंडस्ट्री भी बताई जो लगी हैं और नयी लगेंगी उन का भी बताया । जहां तक डेरी . . .

**श्री सभापति** : वह भी आप ने कहा ।

**श्री नारायण दत्त तिवारी** : नहीं कहा ।

**श्री नारायण दत्त तिवारी** : डेरी उद्योग का सम्बन्ध सदस्य जानते हैं उद्योग विभाग से नही है, कृषि विभाग से है । फिर भी टेक्नो-इकानामिक सर्वे के आधार पर जो उद्योग लग सकते है उन के विषय में उत्तर प्रदेश सरकार से विचार-विमर्श चल रहा है । जौनपुर नान-इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है इस लिए उस के अधिक विकास की सम्भावनाएं विद्यमान है ।

**श्री शिव चन्द्र झा** : बलिया जिला ही सब से नीचे नही है । उस से भी नीचे जिले है डेवलपमेंट के ख्याल से और वे जिले है उत्तरी बिहार के जिले । यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त की रिपोर्ट है और मैं समझता हूं कि अब वह आउट आफ डेट हो गयी है ।

**श्री रामेश्वर सिंह** : नहीं हुई है ।

**श्री सभापति** : आप उन पर हमला मत करिए । (व्यवधान) इधर भी वही, उधर भी वही, सुना है कि बराबर को टक्कर हुई ।

**श्री शिव चन्द्र झा** : अब रिपोर्ट बनायी जायेगी तो पता चलेगा कि जब पिछली रिपोर्ट लिखी गयी थी तब से बलिया जिला और भी नीचे चला गया है, इसलिए वह आउट आफ डेट हो गयी है । डेवलपमेंट का काम अनबैलेंस्ड चल रहा है । उत्तरी बिहार प्रधान मंत्री

गयी हैं, प्रधान मंत्री ने उत्तरी बिहार हेलीकोप्टर से देखा है, जमीन पर चल कर नहीं देखा। उत्तरी बिहार में आम और लीची का भंडार है, हिन्दुस्तान जानता है, दुनिया जानती है। इसलिए वहां आम और लीची की कैनिंग फैक्ट्री मजे में वायेबिल हो सकती है, बनायी जा सकती है। मैंने सवाल भी किया पर सरकार इस पर क्यों नहीं ध्यान देती कि कैनिंग फैक्ट्री आम और लीची की उत्तरी बिहार में मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधुबनी में लगाई जाये ताकि उस का डेवलपमेंट हो और वह भी दूसरे जिलों के मुकाबले आ सकें। यह बताइये कि सबसे लोएस्ट जिले कौन से हैं डेवलपमेंट के ख्याल से ताकि देश को पता चल सके सब से नीचे कौन है, उस के ऊपर कौन है, उस के ऊपर कौन है।

**श्री सभापति**: यहां तो इलेक्शन केम्पेन होने लगा। आप इस का जवाब देने से माजूर हैं।

**श्री शिव चन्द्र झा**: आप जवाब दीजिए।

**श्री पी० राममूर्ति**: कह दीजिए ध्यान देंगे।

**श्री सभापति**: तिवारी जी, किसी तरह इस को खत्म करिये। कह दीजिए कि गौर करेंगे।

**श्री नारायण दत्त तिवारी**: हम गौर करेंगे।

SHRI V. GOPALSAMY : He is ready to consider Bihar, but not Tamil Nadu. This is discrimination. I want to put it on record.

**श्री शिव चन्द्र झा**: गौर करने की बात नहीं इस को आप एक्सीपिडाइट कराइये। आप एलान करिये कि आप वहां आम और लीची की कैनिंग फैक्टरी स्थापित करने जा रहे हैं।

SHRI R. RAMAMURTI : I am firmly of the opinion that U. P. being one of the industrially backward States, it must be given all attention. I have no quarrel on that. But it does not mean that other States should be neglected. He has said that one of the new units of the HPF is being located in U. P. he says this is under consideration. But the question is. the HPF factory which is located in Ooty has got all the facilities. Secondly, once you set up this colour film unit in some other place, naturally, the black and white film production will have to go down. This will be because, it will have no market. The factory will have to be closed down or the production will have to be cut down very drastically. This district, Nilgiris district, being already a backward district will become further backward. You should take all these factors into consideration, factor of employment, factor of unutilisation of capacity and also the factor of cost. Already, you have asked the Tamil Nadu Government to acquire the land and they have acquired the land. This has already been done. Taking all these factors into consideration, will you reconsider your decision in regard to the location of the colour film unit?

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : No more questions on this.

SHRI NARAYAN DATT TIWARI : As far as the Ooty unit is concerned, as the hon. Member knows, it does not manufacture only black and white films. But it also manufactures a large number of other products. For example, dental x-rays and medical x-rays and so on. The feasibility report itself has said that there would be considerable scope for the production of black and white films in the future also. I should not anticipate as to what would be the decision of the Board, what would be the recommendation of the Board. I would like to assure the hon. member that there is no question of shifting any of these units and there is no question of any person being

unemployed beacause of the establishment of any new unit in any part of the country.

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Mr. Hashmi I am afraid, you were not in your seat. Question No. 342.

**Selling of IIP expertise to a Party of Iraq**

*342. SHRI B. SATYANARAYAN REDDY:†

DR. BHAI MAHAVIR :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that one Scientist of Indian Insiitute of of Petroleum was caught while selling the Institute expertise to a party in Iraq for a sum of Rs. 1.60 lakhs when the Institute was making a Government to Government collaboration with the same party;

(b) if so, what are the details of the case ; and

(c) what action, if any, has been taken against the Scientist?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ELECTRONICS, OCEAN DEVELOPMENT AND THE DEPARTMENT OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI C.P.N. SINGH) : (a) to (c). No, Sir; However a Scientist of Indian Institute of Petroleum joined the Council of Scientific Research in Iraq without authority. His explanation has been called for.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri B. Satyanarayan Reddy.

**श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी :** सदर साहब, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में कहा कि जो प्रश्न जिस विषय में किया गया है वह सही नहीं है तो मै मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि भारत के एक वैज्ञानिक भारत पेट्रोलियम संस्थान के काम के लिये ईराक गये ? वहां के किसी पार्टी को इस संस्थान की टेक्नालोजी को बेचा या नहीं। ये पकड़े गये है। वे कहते है कि नहीं पकड़े गये हैं। यह टेक्नालाजी बेचने की वहां कोशिश की गई या नही उसको बेचा गया कि नहीं। जब वह वैज्ञानिक वहां गये तो सरकार को इसकी मालूमात है या नहीं? अगर मालूमात है तो सरकार ने उसके बारे में क्या कार्यवाही की? इसकी तफसीलात क्या है इसके बारे में बतायें। यह कहना कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है और यह कहकर बैठ जाना ठीक नहीं है।

**श्री सभापति :** आप बतायें और कैसे कहेंगे। अगर इसमें सच्चाई नहीं है तो और कैसे कहेंगे ?

**श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी :** वह कहते हैं नही पकडा गया है। अगर नहीं पकड़ा गया है तो कोई ऐसी चीज हुई है, बातचीत हुई है बचने के लिए ? शायद 1.60 लाख में इसका मामला हुआ है। तो इस सिलसिले में कहे कि मामला हुआ या नहीं पकड़ा नहीं गया। तो यह बतायें कि असल मामला क्या है, मामला हुआ है तो किस किस्म का, वहां भारत का वैज्ञानिक गया है वह किसलिए ? (व्यवधान) ...

**श्री सभापति :** उन्होंने जो जवाब दिया, उससे पता चलता है .. (व्यवधान)